



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 2007/ज्येष्ठ 18, 1929

No. 153]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 2007/JYAISTHA 18, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2007

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. से आंशिक रूप से विन्यासित यार्न (पीओवाई) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/10/2005-डीजीएडी.-1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

2. यतः मेसर्स एमोसिएशन ऑफ सिन्थेटिक फाइबर इण्डस्ट्रीज (जिन्हें एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंशिक रूप से विन्यासित यार्न (पीओवाई) के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उत्पादकों नामतः मेसर्स आफोर्ज इण्डस्ट्रीज लि., मेसर्स अपोलो फाइबर्स लि., मेसर्स सेन्ट्रल इण्डिया पोलीएस्टर्स लि. मै. सेंचुरी एंका लि. मै. फिलाटैक्स इंडस्ट्रीज लि., मै. गार्डन सिल्क मिल्स लि., मेसर्स इण्डोरामा सिन्थेटिक्स (इण्डिया) लि., मै. जे.बी. एफ. लि., मै. मार्टिन पेट्रोफिल्स लि., मै. नाकोडा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि., मेसर्स रेक्रॉन सिन्थेटिक्स लि. तथा मेसर्स वेलस्पन सिंटेक्स लि. की ओर से एक आवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष प्रस्तुत किया है और सम्बद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है;

3. और यतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियमावली के नियम 6 के अनुसरण में कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क के रूप में उस राशि की संस्तुति करने, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के उद्देश्य से सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की ।

अनन्तिम उपाय

4. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2007 के पत्र सं. 14/10/2005-डीजीएडी के माध्यम से सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया ।

क्रियाविधि

5. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है। प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत की सूचना देते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करने के पश्चात ऊपर उल्लिखित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसरण में जांच संबंधी कार्यवाई शुरू करने से पूर्व आवेदक द्वारा पाटन आवेदन प्राप्त होने के बारे में सम्बद्ध देश के दूतावास को भी सूचित किया गया;

(ii) प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की प्रति ज्ञात निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा आवेदक को अग्रेषित की गई और नियम 6(2) के अनुसरण में उन्हें अपने विचार जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अवगत कराने का अवसर भी दिया गया;

(iii) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने के लिए सभी ज्ञात निर्यातकों और चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को एक प्रश्नावली भी अग्रेषित की गयी। जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को सामान्य मूल्य के उचित अनुमान के रूप में ताईवान के संरक्षित सामान्य मूल्य पर आधारित रखा गया। बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत के लिए कीमत के विकल्प के रूप में आवेदक द्वारा नियमावली के अनुबंध -1 के पैरा 7 की शर्त के अनुसार भारत में भुगतान की जाने वाली कीमत के रूप में चीन में सामान्य मूल्य के अनुमान भी उपलब्ध कराए गए थे। जांच शुरुआत के पश्चात प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों को सूचित किया कि चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था मानने के आवेदक के दावे की जांच, प्राधिकारी द्वारा यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा (7) एवं (8) के आलोक में की जाएगी। अतः चीन जन. गण. से सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया कि वे सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वे उक्त पैरा में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं, को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार देने के बारे में प्राधिकारी के विचारार्थ अनुबंध -1 के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित जरूरी सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(iv) ऊपर उल्लिखित नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्रति चीन के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/विनिर्माताओं और सम्बद्ध देश के भारत स्थित दूतावास को उपलब्ध कराई गई :

1. सिक्सी सेंताई केमिकल फाइबर कंपनी लि.
2. जेजियांग सीफू केमिकल फाइबर कम्पनी लि.
3. डब्ल्यू डब्ल्यू टेक्सटाइल कम्पनी लि.
4. हांगजाऊ हुआजिन टेक्सटाइल कम्पनी लि.
5. जिनजियांग सन शाइनिंग टेक्सटाइल्स कम्पनी लि.
6. टोंगकुन ग्रुप जेजियांग हेंगशेंग केमिकल फाइबर कम्पनी लि.
7. हांगजाऊ जोंगली केमिकल फाइबर कम्पनी लि.

(v) जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में चीन के किसी भी निर्यातक/उत्पादक से प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

(vi) नियम 6(2) के अनुसार सम्बद्ध देश चीन के दूतावास को जांच शुरूआत के बारे में सूचित किया गया और उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित अवधि में प्रश्नावली के उत्तर भिजवाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया। निर्यातकों को प्रेषित पत्र, आवेदन तथा प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें भेजी गई थी।

(vii) नियम 6(4) के अनुसरण में सम्बद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को प्रश्नावली सूचनार्थ भेजी गई थी :

1. ऑल इण्डिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन, मुम्बई
2. साऊथ गुजरात टेक्सचराइजर्स वेलफेयर एसोसिएशन, सूरत
3. सनटेक्स इण्डिया
4. गॅलेक्सी टेक्सटाइल्स
5. हारमनी यार्न्स प्रा. लि.
6. ए वी एम एक्सपोर्ट्स
7. गर्ग टेक्स-ओ-फैब लिमिटेड
8. बोधारा पॉलीफैब प्रा. लि.
9. सिल्वासा इण्डस्ट्रीज लि.
10. बीकेलॉन सिन्थेटिक्स लि.
11. आलोक इण्डस्ट्रीज लि.
12. बजारी फिलामेंट्स प्रा. लि.
13. सिद्धवन यार्न्स लि.
14. क्रिम्पलॉन यार्न्स
15. यूनी टेक्स टेक्सचराइजर्स
16. यूनीफाई टेक्सचराइजर्स
17. घमटेक्स (इण्डिया) प्रा. लि.
18. मेहराटेक्स इण्डिया प्रा. लि.
19. एस आर वी पॉलीटेक्स प्रा. लि.
20. सिनफैब्स सेल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.

(viii) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में मेसर्स ऑल इण्डिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन, मुम्बई और फेडरेशन ऑफ इण्डियन आर्ट सिल्क वीविंग इण्डस्ट्री (एफआईएसडब्ल्यूआई) ने अपने विवरण प्रस्तुत किए हैं। उनके विवरणों पर पाटनरोधी जांच की सुसंगत सीमा तक विचार करके उनकी जांच की गई है।

(ix) अन्य हितबद्ध पक्षों ने भी जब अनुरोध किया, उन्हें अगोपनीय आवेदन की प्रति भिजवा दी गई।

(x) नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया और हितबद्ध पक्षों के निरीक्षणार्थ उसे एक सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा गया।

(xi) इस बात के अभिनिश्चय के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने की दृष्टि से पर्याप्त होगा; सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर इष्टतम उत्पादन लागत तथा भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के निर्माण व बिक्री संबंधी लागत की लागत जांच की गई।

(xii) निर्दिष्ट प्राधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 23 अगस्त, 2006 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू उद्योग व अन्य हितबद्ध पक्षों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तथापि, सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान एक हितबद्ध पक्ष ने तर्क दिया कि उन्हें सार्वजनिक सुनवाई की सूचना यथासमय प्राप्त नहीं हुई; अतः उन्होंने एक और सुनवाई के आयोजन का अनुरोध किया। हितबद्ध पक्ष के अनुरोध पर प्राधिकारी दूसरी सुनवाई के लिए सहमत हो गए जिसका आयोजन 20 सितम्बर, 2006 को किया गया। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हितबद्ध पक्षों से मौखिक रूप में व्यक्त उनके विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने अपने प्रकटीकरण में हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित विवरण तथा उनके उत्तरों पर विचार किया है। प्रारम्भिक जांच परिणाम की घोषणा से पूर्व हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों, जिनका विवरण पहले अधिसूचित प्रारम्भिक जांच परिणाम में दिया गया है, को स्थानाभाव के कारण यहां दोहराया नहीं गया है।

(xiii) इस अधिसूचना में **** एक हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना प्रदर्शित करता है, जिसे प्राधिकारी ने उसके गुणों के आधार पर नियमावली के तहत गोपनीय माना है। ऊपर उल्लिखित नियमावली के नियम 16 के अनुसरण में विचारित अनिवार्य तथ्यों/आधारों से ज्ञात हितबद्ध पक्षों को दिनांक 26 अप्रैल, 2007 को अवगत करा दिया गया था और इन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

(xiv) जांच 1 अप्रैल, 2004 से शुरू करके 30 जून, 2005 (15 माह) तक की अवधि अर्थात् जांच अवधि (पीओआई) हेतु की गई। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच हेतु 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा जांच अवधि (पीओआई) को शामिल किया गया।

ख. विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु तथा घरेलू उद्योग

विचाराधीन उत्पाद :

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आंशिक रूप से विन्यासित यार्न है, जिसे सामान्यतः पीओवाई कहा जाता है। यह भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 5402.42 में आता है। यह पॉलिएस्टर का एक यार्न है और एक मध्यवर्ती वस्तु है, जिसे कपड़ा बनाने में बुनाई अथवा नीटिंग के अनुकूल बनाने के लिए आगे की प्रक्रिया उदाहरणार्थ टेक्सचरिंग अथवा ड्रॉ टिवस्टिंग से गुजरना होता है। आयातकों और प्रयोक्ताओं ने तर्क दिया है कि आवेदक ने जिस डेनियर के लिए जांच की मांग की है, उसे विनिर्दिष्ट नहीं किया है क्योंकि इसका उत्पादन व्यापक रेंज में किया जाता है। यह भी तर्क दिया गया है कि सम्बद्ध वस्तुओं का विनिर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं व कच्चे माल से होता है और सम्बद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण कच्चे माल के स्रोत के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदन में विनिर्दिष्ट सम्बद्ध वस्तुओं में सभी प्रकार के डेनियर शामिल हैं और आवेदन में सम्बद्ध

वस्तुओं के डेनियर विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उनका तर्क है कि आयातकों तथा प्रयोक्ताओं के विवरण आधारहीन हैं और गुणविहीन हैं।

7. विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है और जांच के उपरान्त यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के आवेदन में भी डेनियर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी समस्त विचाराधीन उत्पाद पर विचार करते हुए विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्षों के इस विवरण के संबंध में, कि टेफ्लॉन उपचारित पोलिएस्टर यार्न तथा पोलिएस्टर नैनो टेक्नोलॉजी यार्न का उत्पादन याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता, अतः इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए; प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया कि ये यार्न पीओवाई के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इन उत्पादों को आगे और प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा यह भी नोट किया जाता है कि सम्बद्ध देश के निर्यातकों ने उनके द्वारा भारत को निर्यातित तथा निर्यातक देश में बेचे जा रहे विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न ग्रेडों तथा प्रकारों/डेनियरों का विवरण नहीं दिया है। इसके अलावा किसी भी आयातक ने प्राधिकारी को साक्ष्य सहित सूचना नहीं दी है अथवा विचाराधीन उत्पाद की डेनियरवार जांच का अनुरोध प्राधिकारी ने नहीं किया है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर व्यक्त किए गए विचारों की जांच की है और उनका अभिमत है कि विचाराधीन उत्पाद में किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं है, जैसा कि आयातकों/प्रयोक्ताओं ने दावा किया है। अतः प्राधिकारी ने आयातकों/प्रयोक्ताओं के तर्क को उपयुक्त नहीं पाया है। अतः अनंतिम जांच परिणाम में यथा परिभाषित तथा पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद की अनंतिम जांच परिणाम में पुष्टि की जाती है।

समान वस्तु

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

‘समान वस्तु का तात्पर्य ऐसी किसी वस्तु से है जो भारत में पाटन किए जाने हेतु जांचाधीन उत्पाद से हर प्रकार से समनुरूप अथवा समान हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जो हालांकि हर प्रकार से समान नहीं है किन्तु उसकी विशेषताएं जांचाधीन वस्तु की विशेषताओं से अत्यधिक मिलती जुलती हों।’

आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में जिन सम्बद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित सम्बद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यो अथवा अंतिम उपयोग में कोई भिन्नता नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो निर्यातकों और न ही हितबद्ध पक्षों ने इस तथ्य का खण्डन किया है कि पाटित वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई भिन्नता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित वस्तुओं का उपयोग प्रयोक्ता उद्योग द्वारा, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के स्थान पर किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश द्वारा उत्पादित वस्तुएं तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और पाटनरोधी नियमावली के तहत सम्बद्ध देशों से आयातित वस्तुओं के समान ही समान वस्तुएं हैं।

घरेलू उद्योग

9. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(ख) "घरेलू उद्योग" से तात्पर्य उन सभी घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण में अथवा उससे संबंधित कार्यकलाप में संलग्न है अथवा जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात है; सिवाय उस स्थिति के जब ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों और ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा :

यह नोट किया जाता है कि यह आवेदन मेसर्स एसोसिएशन ऑफ सिन्थेटिक फाइबर इण्डस्ट्री, नई दिल्ली द्वारा घरेलू उद्योग जिसमें भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादक शामिल हैं, की ओर से प्रस्तुत किया गया है :-

- I. अरफीस इंडस्ट्रीज लि०
- II. अपोलो फाइबर्स लि०
- III. सेंट्रल इंडिया पॉलिस्टर्स लि०
- IV. सेंचुरी एंका लि०
- V. फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज लि०
- VI. गार्डेन सिल्क मिल्स लि०
- VII. इंडो रामा सिन्थेटिक्स (इंडिया) लि०
- VIII. जेबीएफ लि०
- IX. मॉडर्न पेट्रोफिल्स लि०
- X. नकोडा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लि०
- XI. रेक्रॉन सिन्थेटिक्स लि०
- XII. वेलस्पन सिन्टेक्स लि०

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आवेदन का निम्नलिखित उत्पादकों द्वारा भी समर्थन किया गया है:-

- क. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०
- ख. सांघी पॉलिस्टर्स लि०
- ग. नोवा पेट्रोकेमिकल्स लि०
- घ. गोकुलानन्द पेट्रोफाइबर्स
- ड. राजवी पेट्रोकेम (प्रा०) लि०

11. अनन्तिम जाँच परिणामों के दौरान प्राधिकारी ने नोट किया था कि उपर्युक्त उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर वे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते थे । प्राधिकारी ने यह भी निर्धारित किया था कि उपर्युक्त उत्पादक नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति के

मापदण्ड को पूरा करते हैं। एक हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा किया है कि 'घरेलू उद्योग' का निर्धारण करते समय मै0 वेलस्पन से आयातों की तुलना उनके अपने उत्पादन से की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातकों ने अपने तर्क के समर्थन में कोई संतुष्टिप्रद कारण प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी यह पाया गया है कि चीन जन.गण. के मै0 वेलस्पन से आयात उनके अपने उत्पादन का लगभग 0.1% है जो कि नगण्य मात्रा है और मै0 वेलस्पन को घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने के प्रयोजनार्थ इसे नजरअन्दाज किया जा सकता है।

अन्तिम जाँच परिणामों के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदकों की स्थिति के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में प्राधिकारी के समक्ष कोई वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमानुसार स्थिति संबंधी मानदण्ड को पूरा करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार इस जाँच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग को निर्माण करते हैं।

ग. जाँच की अवधि

12. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी कहा है कि जाँच अवधि 12 महीनों की अर्थात् 2004-05 और न कि 15 महीनों की, जैसा कि इस जाँच में प्राधिकारी द्वारा किया गया है, होनी चाहिए। इस मुद्दे की जाँच की गई है और यह विचार किया गया है कि इस निदेशालय की स्थापित प्रथा के अनुसार जाँच अवधि यथा संभव (जाँच शुरुआत की तारीख के) अद्यतन होनी चाहिए और जाँच अवधि की अंतिम तारीख तथा जाँच शुरुआत की तारीख के बीच का अंतर छह महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया गया है कि यदि जाँच की अवधि 2004-05 ली जाती तो जाँच अवधि और जाँच शुरुआत की तारीख के बीच का अंतर छह महीनों से अधिक होता और यह नीति के अनुरूप नहीं होता। अतः प्राधिकारी द्वारा 15 महीनों की जाँच अवधि का निर्धारण जाँच अवधि को यथासंभव जाँच शुरुआत की तारीख के निकट रखने और किसी भी स्थिति में जाँच शुरुआत की तारीख से छह माह से अनधिक होने तथा एक पूर्ण वित्त वर्ष के रूप में घरेलू उद्योग की सूचना की सहज उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी की प्रथा के अनुरूप है। यह भी नोट किया गया था कि इस जाँच में बड़ी संख्या में घरेलू उद्योग शामिल थे और 12 महीनों के वित्त वर्ष में से 9 महीनों के आँकड़े प्राप्त करने में न केवल प्राधिकारी को बल्कि घरेलू उद्योग को भी कठिनाई होती।

घ. सामान्य मूल्य

13. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश अर्थात् चीन भारतीय पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। अतः चीन के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा-7 में दी गई पद्धति के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। आवेदकों ने दावा किया है कि पैराग्राफ -7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण इनमें से किसी भी अर्थात् बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में घरेलू बिक्री कीमतों या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकल्पित मूल्य या भारत सहित किसी अन्य देश को ऐसे तीसरे देश की निर्यात कीमतों के आधार पर किया जाना अपेक्षित होता है। तथापि, यदि ऊपर उल्लिखित किसी भी विकल्प के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या भुगतान योग्य कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करेंगे।

14. किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रथम विकल्प के रूप में उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश का चयन किया जाना अपेक्षित होता है। जाँच की शुरुआत के समय यह प्रस्ताव किया गया था कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले उचित तीसरे देश के रूप में चीनी ताइपेई को लिया जाए। हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् मै0 ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन और मै0 एफआईएसडब्ल्यूआई ने यह निवेदन किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ ताइवान का प्रतिनिधि देश के रूप में चयन सही नहीं है और ताइवान में परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर निर्धारित चीन का सामान्य मूल्य वास्तविकता से बहुत परे है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अभ्यावेदनों में प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि चीनी ताइपेई को प्रतिनिधि देश के रूप में क्यों नहीं लिया जा सकता है और आवेदक द्वारा चीन के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य स्वीकार्य क्यों नहीं है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि हितबद्ध पक्षकारों के अप्रमाणित दावों को नजरअंदाज किया जाना अपेक्षित है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँचों में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा -7 व 8 के अनुसार किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। चीन के किसी भी उत्पादक ने यह दावा नहीं किया है कि उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जाए। अतः प्राधिकारी नियमों के अनुबंध -1 के पैरा -7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्यवाई करते हैं।

16. यह नोट किया गया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जा सकता है :-

- (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत, या
- (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित सामान्य मूल्य, या
- (ग) भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश की कीमत के आधार पर।
- (घ) यदि ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए उचित रूप से समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या भुगतान योग्य कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करेंगे।

17. आवेदक ने पाटनरोधी नियम के अनुबंध-1 के पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश के रूप में चीनी ताइपेई को लिए जाने का सुझाव दिया था। प्राधिकारी ने भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में चीनी ताइपेई का सुझाव दिया था और जाँच की शुरुआत के समय सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ एवं सूचना आमंत्रित की थी। तथापि, चीनी ताइपेई में विद्यमान कीमतों एवं लागतों के बारे में किसी उत्तर या सूचना के अभाव में इस समय प्राधिकारी के लिए भारतीय पाटनरोधी नियम के अनुबंध-1 के पैरा 7 में दी गई ऊपर उल्लिखित (क) से (ग) पद्धतियों के अंतर्गत चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है। इन परिस्थितियों में, इन प्रारंभिक जाँच परिणामों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के पास नियमों में यथापरिभाषित उचित रूप से समायोजित, भारत में भुगतान की गई या भुगतान-योग्य कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के अतिरिक्त और

कोई विकल्प नहीं है। भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया था, जबकि भारत में विद्यमान खपत संबंधी मानदण्डों, परिवर्तन लागत और अन्य लागतों पर विचार किया गया था। भारत में भुगतान योग्य कीमत का परिकलन करते समय उत्पादन लागत में उचित आय को जोड़ा गया था। प्रारंभिक जाँच परिणामों के बाद प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों पर सवाल करते हुए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। किन्हीं प्रमाणित तर्कों की अनुपस्थिति में प्राधिकारी प्रारंभिक जाँच परिणामों के दौरान प्राधिकारी द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य की (गौण परिवर्तनों के साथ) पुष्टि करते हैं। अतः सामान्य मूल्य **** अम.डा. प्रति मी. टन निर्धारित किया गया है।

द. निर्यात कीमत

18. जाँच की शुरुआत के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन में आवेदक ने डीजीसीआई एण्ड एस आयात आँकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का परिकलन किया था। प्राधिकारी ने भी डीजीसीआई एण्ड एस से आयात आँकड़े प्राप्त किए हैं और प्रारंभिक जाँच परिणामों के दौरान यह पाया गया था कि सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 5402.42 (जो विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित कोड है) के अंतर्गत आयातों की मात्रा एवं मूल्य वही थे, जो आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। सार्वजनिक सुनवाई और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निवेदनों के दौरान यह दर्शाया गया था कि आयात की मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने पीओवाई से इतर यानों के आयातों से संबंधित कई सौदों पर विचार किया था। प्रारंभिक जाँच परिणामों के बाद प्राधिकारी ने संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित सौदे-वार सूचना की पुनः जाँच की थी और यह पाया गया था कि यद्यपि आईटीसीएचएस वर्गीकरण विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित कोड है, तथापि उसमें स्पिन ड्रॉन यार्न तथा फुली ड्रॉन यार्न के कुछ सौदे भी शामिल हैं। जाँच के बाद प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा एवं मूल्य का पुनः परिकलन किया है और पुनः जाँच के बाद, डीजीसीआई एण्ड एस आयात आँकड़ों के अनुसार सीआईएफ निर्यात कीमत **** रूपए प्रति मी. टन (**** अम. डॉलर प्रति मी. टन) निर्धारित की गई थी। समुद्री बीमा, कमीशन, समुद्री भाड़ा, बैंक प्रभार तथा पत्तन व्ययों के लिए कीमत समायोजनों पर विचार करने के बाद निवल निर्यात कीमत **** अम. डॉ. प्रति मी. टन निर्धारित की गई है।

पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत, दोनों का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर किया है। सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत दोनों एक ही अवधि से संबंधित हैं। दोनों कीमतें कर-मुक्त हैं। अतः प्राधिकारी विचार करते हैं कि इस प्रकार की गई तुलना उचित है। ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निवल निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन **** अम. डॉ. प्रति मी. टन निर्धारित किया गया है जो निवल निर्यात कीमत का 63% परिकलित होता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

20. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि चीन से आयातों के हिस्से में न केवल कुल आयातों की तुलना में बल्कि आधार वर्ष अप्रैल, 01- मार्च, 02 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान कुल मांग एवं कुल उत्पादन

की तुलना में भी कई गुना वृद्धि हुई है। यह निवेदन किया गया था कि चीन से पाटित आयातों से घरेलू कीमतें प्रभावित हुई हैं और जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री बहुत अधिक रही है। घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि क्षति जांच अवधि में बाजार हिस्से, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, वृद्धि आदि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है, तथापि बिक्री में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में कम है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि जांच अवधि के दौरान भी चीन से पाटन का मार्जिन बहुत अधिक था जो संबद्ध वस्तु के निपटान में घरेलू उद्योग के समक्ष आई कठिनाइयों को दर्शाता है।

21. दूसरी ओर आयातकों तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने निवेदन किया है कि अन्य देशों के लिए भी पीओवाई की कीमतों में कमी हुई है और देशी उत्पादन की तुलना में वर्ष 2001-02 से ही पीओवाई की कीमत अधिक रही है और देशी उद्योग उत्पाद की कमी उत्पन्न करके लाभान्वित हुआ है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आई गिरावट गौण है और मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि रोजगार तथा वेतन के संबंध में कोई क्षति नहीं हुई है और घरेलू उत्पादकों के तुलनपत्र के अनुसार उन्हें घाटा नहीं हो रहा है और अधिकांश कंपनियाँ लाभ कमा रही हैं।

22. आयातकों तथा प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने यह भी निवेदन किया है कि जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ताओं की वस्तु सूची वस्तुतः पिछले वर्षों की तुलना में कम थी। इसके अतिरिक्त, कच्ची सामग्रियों की कीमत कम थी और चीन, जहाँ कच्ची सामग्रियों की कीमत अधिक और पीओवाई की कीमतें कम हैं, की तुलना में भारत में पीओवाई की कीमतें अधिक हैं। उनका यह भी मत था कि लगभग सभी कंपनियाँ अपनी क्षमता का विस्तार कर रही हैं जो यह दर्शाता है कि पीओवाई के आयात से देशी उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

23. पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 3.1 तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में (क) पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका प्रभाव, (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभावों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान है। प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या आयातक सदस्य देश में समग्र रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत की तुलना में आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

24. प्राधिकारी ने क्षति जांच संबंधी पहलू के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट किया है तथा इस प्रकटन विवरण में उचित स्थानों पर उठाए गए मुद्दों का उस सीमा तक उल्लेख किया है जहां तक उन्हें जांच की दृष्टि से संगत समझा गया है। प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध तथ्यों तथा हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार करके क्षति मानदण्डों पर विचार किया है।

25. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि प्राधिकारी द्वारा "समस्त घरेलू उद्योग" हेतु क्षति एवं एनआईपी का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है और केवल किसी विशेष कंपनी अथवा उद्यम के संबंध में नहीं। अतः उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकारी ने सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों हेतु लागत एवं क्षति संबंधी सूचना मंगवाई थी। तथापि, इन उत्पादकों ने, उक्त निर्णय के विषय में स्वयं की व्याख्या के आधार पर उपर्युक्त विषय के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध कराने से मना कर दिया है।

अन्य ज्ञात उत्पादक (मै. आरआईएल लि.) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय में, एनआईपी तथा क्षति निर्धारण के लिए सभी घरेलू उत्पादकों को शामिल करना अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा अन्य घरेलू उत्पादक ने यह तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रयुक्त "समग्र रूप से घरेलू उद्योग" शब्दों के अर्थ की व्याख्या "समग्र घरेलू उत्पादकों" के रूप में कर रहे हैं। इस संबंध में, मै. आरआईएल द्वारा यह निवेदन किया गया है कि माननीय न्यायालय ने उस निर्णय में कहा था कि क्षति एवं एनआईपी का निर्धारण "समग्र घरेलू उद्योग" के लिए किया जाना चाहिए न कि किसी विशेष कंपनी अथवा उद्यम के लिए। उसी पैराग्राफ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा का उल्लेख किया है। आगे यह बताया गया है कि पूरी बातचीत के दौरान उच्चतम न्यायालय ने "समग्र घरेलू उद्योग" शब्दों का उपयोग किया है न कि "समग्र घरेलू उत्पादकों" का। इसके अतिरिक्त, किसी भी समय पर उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि "घरेलू उद्योग" शब्द की व्याख्या नियम 2(ख) में दी गई परिभाषा से किसी भी अलग प्रकार से की जानी चाहिए। दूसरी ओर, न्यायालय ने उसी पैराग्राफ में "घरेलू उद्योग" की परिभाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

26. प्राधिकारी चोट करते हैं कि माननीय कोर्ट के निर्णय की उपर्युक्त व्याख्या उक्त निर्णय के अनुपालन में नहीं हो सकती है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा दायर समीक्षा संबंधी आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अतः प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के सभी घरेलू उत्पादकों, जहां तक वे युक्तिसंगत ढंग से उपलब्ध थे, को शामिल करते हुए घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति और एनआईपी का निर्धारण किया है। यह नोट किया जाता है कि मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के अलावा अनेक अन्य काफी छोटे घरेलू उत्पादक हैं जो भारत में संबद्ध वस्तु के एक प्रमुख उत्पादक हैं तथा कुल घरेलू उत्पादन में जिनका हिस्सा लगभग 33% है। प्राधिकारी ने प्रमुख उत्पादक मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. की लागत एवं क्षति संबंधी सूचना की जांच कंपनी कार्य मंत्रालय की लागत लेखा परीक्षा शाखा के पास यथा उपलब्ध उसकी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर की है। अन्य अत्यंत लघु घरेलू उत्पादकों के लिए लागत एवं क्षति संबंधी सूचना लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के रूप में या किसी अन्य रूप में उपलब्ध नहीं है। यह नोट किया जाता है कि इन अन्य अत्यंत लघु उत्पादकों का समग्र रूप से कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सा 14% बनता है। अतः इन अत्यंत लघु उत्पादकों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार, क्षति की जांच भारत के कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 86% हिस्सा रखने वाले संबद्ध वस्तु के 11 ज्ञात उत्पादकों के संबंध में प्राप्त सूचना को ध्यान में रखकर की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रत्येक क्षति संबंधी मापदंड के संबंध में समग्र

रूप से घरेलू उद्योग में मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (जिनका कुल हिस्सा 86% है) की सूचना शामिल है लेकिन भारत में सभी उत्पादकों की सूचना शामिल नहीं है। घरेलू उद्योग में केवल आवेदक उत्पादक (जिनके पास 52% हिस्सा है) शामिल हैं। घरेलू उद्योग के लिए समग्र रूप से क्षति संबंधी मापदंडों हेतु क्षति विश्लेषण नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्राधिकारी के पास कुछेक क्षति संबंधी मापदंडों हेतु अपेक्षित सूचना नहीं थी, जिसे अगले पैराग्राफों में प्रत्येक कारक हेतु क्षति विश्लेषण करते समय स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। तथापि, मै. आरआईएल लि. ने लागत निर्धारण संबंधी सूचना प्रस्तुत की है जिसका प्रयोग समग्र रूप से घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत की गणना हेतु किया गया है।

27. नियमों के अंतर्गत यथापरिकल्पित क्षति संबंधी मापदंडों का विश्लेषण निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है :-

आयातों की मात्रा

(i) प्राधिकारी ने डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों में यथा प्रदर्शित संबद्ध वस्तु के आयातों के आधार पर संबद्ध देश से आयातों की मात्रा की जांच की है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार विश्लेषण की पुनः जांच की है और पुनः जांच के आधार पर संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा एवं मूल्य के आंकड़ों को संशोधित किया गया है। यह देखा गया है कि संबद्ध देश से कुल आयातों की मात्रा में 2001-02 में 3.7% से जांच अवधि के दौरान 86% तक की वृद्धि हुई है। समग्र रूप से जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से हुए आयातों में आधार वर्ष 2001-02 में हुए आयातों के स्तर के लगभग 22 गुना तक की वृद्धि हुई है।

	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	1461	1455	8693	32132
अन्य देशों से आयात - जिन पर एडीडी लागू है	33256	41046	15891	3856
शेष अन्य देशों से आयात	4797	2886	2253	1413
कुल आयात (मी. टन)	39514	45387	26837	37401

%	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	3.70	3.21	32.39	85.91
अन्य देशों से आयात - जिन पर एडीडी लागू है	84.16	90.44	59.21	10.31
शेष अन्य देशों से आयात	12.14	6.36	8.40	3.78
कुल आयात (मी. टन)	100.00	100.00	100.00	100.00

कुल आयात एवं माँग में संबद्ध देशों से हुए आयातों का बाजार हिस्सा

(ii) प्राधिकारी पाते हैं कि भारत में कुल माँग की तुलना में चीन से हुए आयातों में 2001-02 के दौरान 0.23% के निम्न स्तर से जाँच अवधि के दौरान 4.19% तक की वृद्धि हुई है। वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

कुल माँग	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जाँच अवधि (वार्षिकीकृत)
कुल माँग (मी. टन)	646810	683470	708597	766477
प्रवृत्ति	100	106	110	119

आयातों का हिस्सा	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जाँच अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	1461	1455	8693	32132
अन्य देशों से आयात - जिन पर एडीडी लागू है	33256	41046	15891	3856
शेष अन्य देशों से आयात	4797	2886	2253	1413
कुल आयात (मी. टन)	39514	45387	26837	37401
कुल घरेलू बिक्रियाँ (मी. टन)	642012	680584	706344	765063
कुल माँग (मी. टन)	646810	683470	708597	766477
निम्न में चीन के आयातों का % हिस्सा				
कुल आयात	4%	3%	32%	86%
कुल माँग (मी. टन)	0.23%	0.21%	1.23%	4.19%
अन्य देशों से आयातों का प्रतिशत हिस्सा जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है				
कुल आयात	84.16%	90.44%	59.21%	10.31%
कुल माँग (मी. टन)	5.14%	6.01%	2.24%	0.50%
निम्न में शेष अन्य देशों से आयातों का % हिस्सा				
कुल आयात	12.14%	6.36%	8.40%	3.78%
कुल माँग (मी. टन)	0.74%	0.42%	0.32%	0.18%

घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में संबद्ध देश से आयात

(iii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से हुए आयातों में घरेलू उत्पादकों के घरेलू उत्पादन के प्रतिशत रूप में कई गुना वृद्धि हुई है और ये वर्ष 2001-02 में 0.19% के स्तर से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 3.43% हो गए हैं। इस प्रकार चीन से हुए आयातों में न केवल समग्र रूप से बल्कि भारत में कुल आयातों, बाजार मांग और घरेलू उत्पादन के हिस्से के रूप में भी वृद्धि हुई है।

आयातों का हिस्सा	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात (मी. टन)	1461	1455	8693	32132
अन्य देशों से आयात - जिन पर एडीडी लागू है	33256	41046	15891	3856
शेष अन्य देशों से आयात	4797	2886	2253	1413
कुल आयात (मी. टन)	39514	45387	26837	37401
कुल घरेलू बिक्रियाँ (मी. टन)	642012	680584	706344	765063
कुल माँग (मी. टन)	646810	683470	708597	766477
कुल घरेलू उत्पादन	784460	840065	900245	936775
निम्न में चीन का प्रतिशत हिस्सा				
कुल आयात	4%	3%	32%	86%
कुल माँग (मी. टन)	0.23%	0.21%	1.23%	4.19%
कुल घरेलू उत्पादन	0.19%	0.17%	0.97%	3.43%

समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव

कीमत कटौती

(iv) घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के कारण भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना था या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना था जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती। संबंधित उत्पाद के लिए व्यापार के समान स्तर पर असंबंधित उपभोक्ताओं को की गई बिक्रियों हेतु सभी छूटों और करों के निवल मूल्य पर निर्यातित उत्पाद घरेलू बाजार हेतु घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य की तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखाना द्वार स्तर पर किया गया है। संबंधित संबद्ध देश की सीआईएफ कीमतों को आयात के बाद लागू शुल्कों सहित समायोजित किया गया था। इस तुलना से पता चला कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश में उद्भूत संबद्ध वस्तुओं को भारतीय बाजार में ऐसी कीमतों पर बेचा गया था जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होती है जब उन्हें घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जैसाकि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है।

घरेलू बाजार में आयातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों का विश्लेषण किया गया है। यह नोट किया गया था कि संबद्ध देश से निर्यातकों ने अपनी कीमतें घटा दी थी और क्षति अवधि के दौरान पहुंच मूल्य में 9% की कमी हुई है। यद्यपि इस अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमतों में भी ***% की वृद्धि हुई है, तथापि क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती में भारी वृद्धि हुई है और यह जांच अवधि के दौरान भी अधिक रही है।

कीमत कटौती	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
बिक्री कीमत रु./मी. टन- समग्र घरेलू उद्योग	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	112	120	130
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य रु./मी. टन	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	110	86	91
कीमत कटौती रु./मी. टन	****	****	****	****
कीमत कटौती (%)	****	****	****	****
कीमत	-12% से 1%	-8 से 5%	16% से 30%	20% से 48%
कीमत कटौती (%)— रेंज				

कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण

(v) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कोई गिरावट नहीं आई है। अतः घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई ह्रास नहीं हुआ है। तथापि, यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पहुंच कीमत में संबद्ध देश से लगातार कमी हुई है और घरेलू बिक्री कीमत के साथ उत्पादन लागत में भी तदनुरूपी वृद्धि हुई है (घरेलू बिक्री कीमत से मामूली अधिक) जिसका यह अर्थ है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण का सामना करना पड़ा है।

	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
उत्पादन लागत रु./मी. टन- घरेलू उद्योग- समग्र रूप से	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	108	104	132
वर्षवार वृद्धि		****	****	****
सूचीबद्ध		100	-58	591
बिक्री कीमत रु./मी. टन- घरेलू उद्योग- समग्र रूप से	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	112	120	130
वर्षवार वृद्धि		****	****	****
सूचीबद्ध		100	76	112
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य- रु./मी. टन	56137	61537	48429	50997
सूचीबद्ध	100	110	86	91

कीमत कटौती

(vi) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे की जांच भी की है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की बिक्री से कम कीमत पर बिक्री के कारण हानि उठा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत की गणना की है तथा इसकी कम कीमत पर बिक्री की सीमा ज्ञात करने के लिए पहुँच मूल्य से तुलना की है। विश्लेषण कम कीमत पर बिक्री के अत्यधिक उच्च स्तर की घटना को दर्शाता है जिससे संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

कम कीमत पर बिक्री	
	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
क्षति रहित कीमत रुपये/मी.टन	■
चीन से पहुँच मूल्य रुपये/मी.टन	50996
कम कीमत पर बिक्री रुपये/मी.टन	****
कम कीमत पर बिक्री (%)	****
कम कीमत पर बिक्री (%) - सीमा	25% to 40%

घरेलू उद्योग की स्थिति

(vii) भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा तथा मार्जिन जैसे संकेतकों जिनसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, पर गौर किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तर्ज पर प्राधिकारी ने समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए क्षति तथा एन आई पी के निर्धारण के लिए आगे कार्रवाई की है ताकि उस सीमा तक जहां तक ऐसा करना प्रासंगिक तथा तार्किक रूप से उपलब्ध हो, संबद्ध वस्तु के सभी घरेलू उत्पादकों को शामिल किया जा सके। यह नोट किया जाता है कि मै0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 जो कुल घरेलू उत्पादन में लगभग 33 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, से पृथक अनेक बहुत छोटे घरेलू उत्पादक हैं। प्राधिकारी ने प्रमुख उत्पादक मै0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 की लागत एवं क्षति की जांच, कंपनी मामले मंत्रालय की लागत लेखा परीक्षा शाखा के पास उपलब्ध इसकी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों से की है। अन्य बहुत छोटे घरेलू उत्पादकों के लिए लागत एवं क्षति जांच संबंधी सूचना, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों के रूप में अथवा अन्य किसी रूप में उपलब्ध नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि ये अन्य अति लघु उत्पादक समग्र रूप से कुल घरेलू उत्पादन का 14 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। इसलिए, इन अति लघु

उत्पादकों का प्रभाव उल्लेखनीय नहीं होगा। तदनुसार, भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा बनाने वाले 11 ज्ञात उत्पादकों से संबंधित जानकारी के आधार पर क्षति जांच की गई है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति संबंधी मापदण्डों में से प्रत्येक के संबंध में समग्र रूप से घरेलू उद्योग में मै0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 की जानकारी शामिल है किन्तु भारत में सभी उत्पादकों की जानकारी शामिल नहीं है। 'घरेलू उद्योग' प्रत्यय में केवल याचिकाकर्ता उत्पादक शामिल है। समग्र रूप से घरेलू उद्योग हेतु क्षति संबंधी सभी मापदण्डों के लिए क्षति विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि क्षति संबंधी मापदण्डों से कुछेक के लिए अपेक्षित सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी जिसे प्रत्येक कारक के लिए क्षति विश्लेषण करते समय स्पष्ट रूप से निम्नलिखित पैराग्राफों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

बिक्री और घरेलू उत्पादक का बाजार हिस्सा

(viii) यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग तथा समग्र रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है तथा यह वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग तथा भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा निम्नानुसार रहा है:-

बिक्री (मी.टन)	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अबधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	307826	310022	324328	392195
अन्य घरेलू उत्पादक	202429	175147	234039	231456
समग्र रूप से घरेलू उद्योग	510255	485169	558367	623651

घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अबधि (वार्षिकीकृत)
बिक्री (मी.टन)				
घरेलू उद्योग	307826	310022	324328	392195
अन्य घरेलू उत्पादक	202429	175147	234039	231456
समग्र रूप से घरेलू उद्योग	510255	485169	558367	623651
कुल मांग (मी.टन)	646810	683470	708597	766477
बाजार हिस्सा:				
घरेलू उद्योग का (%)	48	45	46	51
अन्य घरेलू उत्पादकों का (%)	31	26	33	30
समग्र रूप से घरेलू उद्योग का (%)	79	71	79	81

प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उत्पादक का हिस्सा 2001-02 के दौरान 48 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 51 प्रतिशत हो गया जबकि समग्र रूप से घरेलू उद्योग के हिस्से में इसी अवधि के दौरान 2 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि हुई। यह भी नोट किया जाता है कि इसी अवधि के दौरान मांग में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान भले ही मामूली रूप से, वृद्धि प्राप्त करने में समर्थ था।

उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

(ix) घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा क्षमता उपयोग निम्नानुसार रहा है:-

उत्पादन (मी.टन)

<u>उत्पादन (मी.टन)</u>				
	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	385167	402651	423669	484734
अन्य घरेलू उत्पादक	269188	247679	255620	252412
समग्र रूप से घरेलू उद्योग	654355	650330	679289	737146

क्षमता (मी.टन)

	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	389425	428175	478196	513208
अन्य घरेलू उत्पादक	267174	275274	268450	261979
समग्र रूप से घरेलू उद्योग	656599	703449	746646	775188

क्षमता उपयोग %

	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	98.91%	94.04%	88.60%	94.45%
अन्य घरेलू उत्पादक	100.75%	89.98%	95.22%	96.35%
समग्र रूप से घरेलू उद्योग	99.66%	92.45%	90.98%	95.09%

प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2001-02 में 98.91 प्रतिशत से जांच अवधि के दौरान 94.45 प्रतिशत तक की गिरावट आई। अतः क्षमता उपयोग में गिरावट

तथा दूसरी ओर क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग प्रतिकूलतः प्रभावित प्रतीत होता है।

माल सूची:

(x) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की माल सूची का स्तर जांच अवधि के दौरान घट गया जबकि बिक्री के प्रतिशत के रूप में माल सूची में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट आई।

मालसूची	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
बिक्री (मी.टन) - घरेलू उद्योग	307826	310022	324328	392195
मालसूची - घरेलू उद्योग	29632	29605	21878	6887
बिक्री के प्रतिशत के रूप में मालसूची	9.63%	9.55%	6.75%	1.76%
सूचीबद्ध	100	99	70	18

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक:

(xi) प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के परिणामस्वरूप कीमत कटौती का स्तर उल्लेखनीय है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री भी सुस्पष्ट है क्योंकि चीन से आयातों का पहुँच मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना में काफी कम है। चीन से आयातों का पहुँच मूल्य/मी.टन में वर्ष 2002-03 की तुलना में जांच अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है जबकि इसी समय कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के परिणामस्वरूप कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के अलावा, भारत में घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के कुछ दूसरे घरेलू उत्पादक हैं जो कुल उत्पादन का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा बनते हैं। इन उत्पादकों के आंकड़े (जो कुल उत्पादन का 23 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं) घरेलू उत्पादकों के बीच लागत तथा कीमत संबंधी उल्लेखनीय अंतर को प्रदर्शित नहीं करते। तथापि क्षति संबंधी जांच अन्य ज्ञात निर्यातकों सहित समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योगों की कीमतों पर उल्लेखनीय कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री संबंधी प्रभाव पाए गए हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। अतः घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रधान कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पाटित कीमतें प्रतीत होता है।

पाटन के मार्जिन का परिमाण:

(xii) प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन के मार्जिन का परिणाम उल्लेखनीय है।

रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता:

(xiii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताएं जोड़ी हैं तथा अनेक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। तदनुसार, कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें प्रदान की गई मजदूरी में क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष 2001-02 की तुलना में वृद्धि हुई है।

कर्मचारी, मजदूरी तथा उत्पादकता

	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
कर्मचारी (सं०) घरेलू उद्योग	3254	3398	3434	3758
मजदूरी (लाख रु.) घरेलू उद्योग	3413	3521	3825	4495
घरेलू उद्योग का उत्पादन	385167	402651	423669	484734
उत्पादकता प्रतिकर्मचारी/मी.टन	118	118	123	129

लाभप्रदता

(xiv) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान लाभ कमाने में असमर्थ रहा है। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2001-02 में 1.30 प्रतिशत के लाभ स्तर को छुआ जो कि जांच अवधि के दौरान नकारात्मक स्तर (0.80 प्रतिशत) तक गिर गया जिसे निम्नानुसार तालिका में देखा जा सकता है:-

लाभ/हानि (लाख रु.)				
घरेलू उद्योग	****	****	****	****
अन्य घरेलू उत्पादक	****	****	****	****
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	****	****	****	****
सूचीबद्ध				
घरेलू उद्योग	100	261	603	-103
अन्य घरेलू उत्पादक	-100	-66	198	-62
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	-100	-27	359	-96
लाभ/हानि (%):				
घरेलू उद्योग	****	****	****	****
अन्य घरेलू उत्पादक	****	****	****	****
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	****	****	****	****

निवेश (लगाई गई पूंजी) पर आय

(xv) प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाई गई पूंजी पर आय में भी गिरावट आई है और इसमें भी लाभप्रदता जैसी ही प्रवृत्ति देखने को मिली। घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान अपने निवेश पर *** % आय अर्जित कर सका जबकि पिछले वर्ष 2003-04 में यह *** % आय तथा आधार वर्ष में *** % आय अर्जित कर सका था।

लगाई गई पूंजी पर आय	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
लगाई गई पूंजी (लाख रु.) - घरेलू उद्योग	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	121	102	102
ब्याज पूर्व लाभ/हानि (लाख रु.) - घरेलू उद्योग	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	98	134	25
आर ओ सी ई (%) - घरेलू उद्योग	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	80.94	131.04	18.66

नकद प्रवाह पर वास्तविक तथा संभावित नकारात्मक प्रभाव

(xvi) प्राधिकारी पाते हैं कि नकद लाभ/नकद प्रवाह में भी लाभप्रदता जैसी ही प्रवृत्ति देखने में आई है तथा आधार वर्ष 2001-02 की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें अत्यधिक गिरावट आई है।

नकद लाभ	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
नकद लाभ (लाख रु.) - घरेलू उद्योग	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	138	190	87
अन्य ज्ञात उत्पादकों का नकद लाभ	****	****	****	****
सूचीबद्ध	-100	-7	1337	9
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	165	509	107.

वृद्धि

(xvii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई तथापि जांच अवधि के दौरान बिक्री मात्रा में वृद्धि पिछले वर्ष तथा इसी अवधि में कुल मांग में वृद्धि की तुलना में कम थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है।

वृद्धि	अप्रैल 01 से मार्च 02	अप्रैल 02 से मार्च 03	अप्रैल 03 से मार्च 04	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
मांग		6	10	19
उत्पादन - समग्र रूप से घरेलू उद्योग		-1	4	9
बाजार हिस्सा - समग्र रूप से घरेलू उद्योग		-10	-0.11	3
बिक्री मात्रा - समग्र रूप से घरेलू उद्योग		-5	15	12
लाभ - समग्र रूप से घरेलू उद्योग		-28	336	-89
नकद प्रवाह/मी. टन - समग्र रूप से घरेलू उद्योग		65	208	-79
आर ओ सी ई - घरेलू उद्योग		-19	62	-86

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

(xviii) प्राधिकारी यह पाते हैं कि पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में वहन किए गए घाटे के दृष्टिगत जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकारात्मक लाभों और घटते हुए लाभों के मद्देनजर घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

छ. कारणात्मक संबंध एवं अन्य कारक**पाटित आयातों के प्रभाव**

28. वर्ष 2001-02 और पी ओ आई के बीच संबद्ध वस्तु के कुल आयात के प्रतिशत के रूप में संबद्ध देश से पाटित आयात 4 प्रतिशत से अत्यधिक बढ़कर 86 प्रतिशत हो गए हैं। कुल मांग की तुलना में चीन से आयातों के प्रतिशत हिस्से में भी जांच अवधि के दौरान बढ़ोतरी हो रही है। यह वर्ष 2001-02 में 0.23 प्रतिशत से बढ़कर पी ओ आई में 4.19 प्रतिशत हो गया है। कीमत प्रभाव की जांच करते समय अर्थात् क्या पाटित आयातों से भारत में संबद्ध वस्तु की कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है प्राधिकारी ने पाया कि चीन से संबद्ध वस्तु का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री

कीमत से कम था जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में अत्यधिक कटौती हुई। यह पाया गया है कि कीमत कटौती और आयातों के पहुँच मूल्य के कीमत व्यवहार से घरेलू उद्योग को घरेलू कीमतें उत्पादन लागत से भी कम अलाभकारी स्तर पर रखने को बाध्य होना पड़ा है जिससे घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उत्पादन लागत में पूर्ण वृद्धि वसूल करने के लिए बिक्री कीमत में बढ़ोतरी नहीं कर सका और पी ओ आई के दौरान उसे वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। कीमत मंदीकरण के साथ कीमत कटौती के प्रभाव से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आयी है। इसके अलावा, आधार वर्ष 2001-02 में सकारात्मक लाभप्रदता की तुलना में पी ओ आई में लाभप्रदता में नकारात्मक स्तर तक कमी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक स्पष्ट सूचक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2003-04 में लाभ क्षति जांच अवधि के अन्य वर्षों की तुलना में लाभ से अधिक रहा है, उस वर्ष में लाभप्रदता में वृद्धि मुख्यतः चीन से कम आयातों के कारण हुई है जिससे घरेलू उद्योग को बेहतर कीमतें वसूल करने और घरेलू बाजार में मार्जिनों में सुधार करने की अनुमति मिल गई होगी। घरेलू उद्योग की तत्काल अगले वर्ष अर्थात् पी ओ आई में लाभप्रदता में चीन से इसी अवधि की तुलना में लगभग चार गुणा उच्च पाटित कीमतों पर आयातों में हुई वृद्धि के मद्देनजर तीव्र गिरावट आयी है। पूर्वोक्त के आधार पर यह माना गया है कि घरेलू उद्योग को पी ओ आई के दौरान चीन से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

अन्य कारकों का प्रभाव

व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

29. प्राधिकारी ने ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं पायी है जिसका भारतीय उत्पादकों और अन्य प्रतिस्पर्धी उद्योगों द्वारा अनुसरण किया गया हो। जहाँ तक घरेलू मांग और उनके अपने उत्पादन के बीच अंतर को पाटने की घरेलू उद्योग की असमर्थता का संबंध है, यह देखा गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं और उत्पादकों पर कोई प्रतिबंध लगाने के समान नहीं हैं, जिससे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में योगदान मिलेगा। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा उचित कीमत पर होती है तो स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता है।

मांग में संकुचन और खपत की पद्धति में परिवर्तन

30. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन अवधि में मांग में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत पी ओ आई में समग्र मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए मांग में संभावित कमी ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी।

प्रौद्योगिकी

31. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस बात का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रौद्योगिकी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारक है।

निर्यात निष्पादन

32. घरेलू उद्योग ने जांच अवधि और पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में सुधार प्रदर्शित हुआ है। क्षति जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू और निर्यात बिक्रियों की लाभप्रदता को अलग-अलग किया गया है। इसलिए निर्यातों के कारण हुई क्षति (यदि कोई हो) को घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया है।

उत्पादकता

33. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में आधार वर्ष 2001-02 की तुलना में जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है। उत्पादकता स्वयं घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

अन्य तर्क

34. कुछेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पी ओ वाई हेतु मांग घरेलू उत्पादन की तुलना में वर्ष 2001-02 से ही उच्च रही है और घरेलू उद्योग कमी उत्पन्न करके अत्यधिक लाभान्वित हुआ है। प्राधिकारी ने इस कथन की जांच की है और वे नोट करते हैं कि एसोसिएशनों ने अपनी दलील के समर्थन में बिना किसी साक्ष्य और अकाट्य तर्क के केवल वक्तव्य दिए हैं। जहां तक उनके अन्य तर्कों कि घरेलू उत्पादकों के तुलन-पत्रों के अनुसार उन्हें घाटा नहीं हो रहा है और अधिकांश कंपनियां लाभ कमाने वाली कंपनियां का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी जांच उत्पाद विशिष्ट होती हैं और कंपनी के तुलन पत्र जिसमें अन्य उत्पादों के संबंध में भी जानकारी होती है, पर आधारित कोई निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है। यह स्थिति पाटनरोधी कानूनों और अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों से स्पष्ट है। जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों कि लगभग सभी कंपनियां अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रही हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि पी ओ वाई के आयात से घरेलू उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ा है, का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि कुछेक आवेदक वास्तव में अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहे हैं यह एक ऐसा तथ्य है जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि क्षमताओं में बढ़ोतरी करने का निर्णय जांच शुरू करने से पहले लिया गया था और विशिष्ट समय के दौरान घरेलू उद्योग को चीन से हुए पाटन के क्षतिकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा था। इस मुद्दे की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि क्षमताओं में वृद्धि बढ़ते हुए बाजार और पैमाने की मितव्ययिताओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इसलिए

केवल इस तथ्य से कि घरेलू उद्योग के कुछ संघटकों ने अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी की है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उन्हें संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घाटा नहीं हो रहा है। जहां तक विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन कि इन वर्षों के दौरान पी ओ वाई पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है और इसे ग्राहकों को हस्तांतरित नहीं किया गया है, का संबंध है यह नोट किया जाता है कि बिक्री कीमतों का विश्लेषण हमेशा कारखाना द्वार स्तर पर किया जाता है। कारखाना द्वार कीमत में उत्पाद शुल्क का कोई अवयव अथवा कारखाने से निकासी के बाद के खर्च शामिल नहीं होते हैं। इसलिए परिसंघ के वक्तव्य को इस जांच में प्रासंगिक नहीं पाया गया है।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष

35. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में कुल मांग एवं घरेलू उत्पादन के संबंध में बढ़ोतरी हुई है। तथापि कुल मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, मालसूची जैसे मानदंडों में कोई गिरावट प्रदर्शित नहीं हुई है जिससे घरेलू उद्योग और समग्र घरेलू उद्योग को अत्यधिक मात्रा संबंधी क्षति होने की अनुपस्थिति का संकेत मिलता है। तथापि, घरेलू उद्योग को कीमत प्रभावों के कारण अत्यधिक घाटा हुआ है क्योंकि कीमत कटौती जो आधार वर्ष के दौरान नकारात्मक थी, पी ओ आई के दौरान सकारात्मक और अत्यधिक हो गई थी। संबद्ध देश से पाटित संबद्ध वस्तु की पहुँच कीमतों में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि जिसे कीमत मंदीकरण का संकेत मिलता है के बावजूद निरन्तर गिरावट प्रदर्शित हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद हेतु घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच अवधि के दौरान नकारात्मक हो गई है और निवेश पर आय और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसमें जांच अवधि में निम्न स्तर तक गिरावट आई है। संबद्ध देश से पाटन मार्जिन अत्यधिक माना गया है। पूर्वोक्त के आधार पर यह माना गया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जैसा कि नियमों के अंतर्गत परिकल्पना की गई है। संबद्ध देश से पाटित आयातों से इतर कोई अन्य कारक प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

36. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

क्षति मार्जिन की मात्रा

क्षतिरहित कीमत का निर्धारण

37. प्राधिकारी ने पूर्व में यथा उद्धृत भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार समग्र घरेलू उद्योग हेतु क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया था और घरेलू उद्योग को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण की विधि का विस्तृत खुलासा किया गया था।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र रूप से घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विधि को ध्यान में रख कर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया गया है और समग्र घरेलू उद्योग हेतु भारत औसत क्षतिरहित कीमत का निर्धारण *** रूपए/मी.टन के रूप में किया गया है।

39. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की सभी किस्मों का भारत औसत है और क्षति मार्जिन के निर्धारणार्थ इसकी तुलना संबद्ध देशों से निर्यातों के भारत औसत पहुँच मूल्य के साथ की गई है। संबद्ध देशों से निर्यातों की भारत औसत पहुँच कीमत और क्षति मार्जिनों का निम्नानुसार परिकलन किया गया है:-

क्षति मार्जिन संबंधी गणनाएं		
कंपनी का नाम	क्षति मार्जिन अम.डा./मी.टन	क्षति मार्जिन %
चीन जन.गण. से सभी उत्पादक एवं निर्यातक	****	30-40%

भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

40. प्राधिकारी मानते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनर्स्थापित करने को सुकर बनाया जा सके।

41. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है तथापि इन पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे और घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और उपभोक्ताओं हेतु संबद्ध वस्तु की व्यापक पसंद की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी।

ट. निष्कर्ष

42. पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि:

क. संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात उनके सामान्य मूल्यों से कम कीमत पर किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ग. घरेलू उद्योग की क्षति संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

घ. अतः प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 54 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की अनुशंसा करना आवश्यक समझते हैं।

ठ. सिफारिश

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई थी और निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं पाटन और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की अंतिम जांच शुरू करने और पूरा करने के बाद और संबद्ध देश के विरुद्ध निश्चित रूप से सकारात्मक पाटन मार्जिन और ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति स्थापित करने के पश्चात प्राधिकारी का विचार है कि पाटन एवं क्षति को निष्प्रभावी करने के लिए निश्चयात्मक शुल्क लगाना अपेक्षित है।

44. अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर नीचे विनिर्दिष्ट विधि एवं ढंग से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

45. प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा करते हैं। तदनुसार, चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 के अंतर्गत आने वाले पार्शली ओरिएन्टेड यार्न के आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.सं.	उप-शीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402.42	पार्शली ओरिएन्टेड यार्न - सभी किस्में	कोई	चीन जन. गण	कोई	कोई	कोई	545.22	मी. टन	अम. डा.
2.	-वही-	-वही-	-वही-	कोई	चीन जन. गण	कोई	कोई	545.22	मी. टन	अम. डा.

ड. आगे की प्रक्रिया

46. केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील जो इस सिफारिश से उत्पन्न हो सकती है, इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

47. प्राधिकारी यहाँ यथा-अनुशंसित निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, इसमें परिवर्तन करने अथवा इसे समाप्त करने की जरूरत की अधिनियम के संगत प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार समय-समय पर समीक्षा कर सकते हैं। ऐसी किसी समीक्षा के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक इसे किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के अनुसार दाखिल न किया गया हो।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2007

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of Partially Oriented Yarn (POY) from China PR.

No. 14/10/2005-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof :

2. Whereas M/s Association of Synthetic Fibre Industries (hereinafter referred to as the Applicant) on behalf of domestic producers namely M/s Arfees Industries Ltd., M/s Appollo Fibres Ltd., M/s Central India Polyesters Ltd., M/s Century Enka Ltd., M/s Filatex Industries Ltd., M/s Garden Silk Mills Ltd., M/s Indo Rama Synthetics (India) Ltd., M/s JBF Ltd., M/s Modern Petrofils Ltd., M/s Nakoda Textiles Industries Ltd., M/s Recron Synthetics Ltd. and M/s Welspun Syntex Ltd, filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act and the AD Rules, alleging dumping of Partially Oriented Yarn (herein after referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (herein after referred to as subject country) and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of anti- dumping duties on the subject goods.

3. And whereas the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 13th December 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary initiating Anti- Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with the Rule 6 of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PROVISIONAL MEASURES

4. The Authority imposed a provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from subject country vide No.14/10/2005-DGAD on 4th July 2006.

A. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation. After issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigations by the Authority, the Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of dumping application made by the Applicant before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

ii) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers/users and to the applicant and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the publication of initiation notification in accordance with the Rule 6(2):

iii) A questionnaire for according market economy treatment was forwarded to all the known exporters and the Embassy of the Peoples' Republic of China. For the purpose of initiation, normal value had been based on the basis of constructed normal value in Taiwan as appropriate estimate of normal value. In an alternate to the price from a market economy third country to India, applicant had also provided estimates of normal value in China as price payable in India in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. Subsequent to initiation, the Authority informed the known exporters that the Authority proposed to examine the claim of the applicant of treating China as non-market economy in the light of paras (7) & (8) of Annexure-I of the Anti-Dumping Rules as amended. The concerned exporters / producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information / sufficient evidence as mentioned in paragraph 8 of Annexure-I to enable the Designated Authority to consider whether market economy treatment could be granted to cooperating exporters / producers who could demonstrate that they satisfied the criteria stipulated in the said paragraph.

iv) According to sub-rule (3) of Rule 6 supra, the Authority provided a copy of the application to the following known exporters/manufacturers from China and Embassy of subject country in India;

1. Cixi Santai Chemical Fibre Co., Ltd.
2. Zhejiang Cifu Chemical Fiber Co., Ltd.
3. W.W Textile Co., Ltd.
4. Hangzhou Huaxin Textile Co., Ltd.

5. Xinxiang Sunshining Textiles Co., Ltd.
6. Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fibre Co., Ltd.
7. Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co., Ltd.

v) In response to the initiation notification none of the exporter/producer from China responded to the questionnaire.

vi) The Embassy of the subject country, China, was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, application and questionnaire was sent to the exporters was also sent to them;

vii) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):

1. All India Texturisers Association, Mumbai
2. South Gujarat Texturisers Welfare Association, Surat
3. Suntex India
4. Galaxy Textiles
5. Harmony Yarns PVT. Ltd.
6. AVM Exports
7. Garg Tex-O-Fab Ltd.
8. Boghara Polyfab Private Ltd.
9. Silvassa Industries Ltd.
10. Beekaylon Synthetics Ltd.
11. Alok Industries Ltd.
12. Bajari Filaments P Ltd.
13. Sidhvan Yarns Ltd.
14. Crimplon Yarns
15. Uni Tex Texturisers
16. Unify Texturisers
17. Ghoomtex (India) Pvt Ltd.
18. Mehratex India P Ltd.
19. SRV Polytex Pvt. Ltd.
20. Synfab Sales and Industries Ltd.

viii) In response to the above notification M/s All India Texturisers' Association, Mumbai and Federation of Indian Art Silk Weaving Industry (FIASWI) have filed their submissions. Their submissions have been taken into account and examined to the extent they have relevant to the anti dumping investigations.

ix) A copy of the non-confidential application was also provided to other interested parties, wherever requested.

x) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file

x) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xi) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xii) A public hearing was held on 23rd August 2006 under the chairmanship of Designated Authority, which was attended by representatives of the Domestic Industry and other interested parties. However, during the process of the hearing, one interested party argued that they did not get the notice of the public hearing in time and hence they requested another public hearing. Following the request of the interested party, the Authority agreed for another hearing, which was held on 20th September 2006. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The Authority in this disclosure has considered the written submissions and rejoinders thus received from interested parties. Arguments raised by interested parties before announcing of preliminary findings, which have been brought out in the Preliminary Findings notified earlier have not been repeated herein for sake of brevity.

xiii) **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered was disclosed to known interested parties on 26th April, 2007 and comments received on the same are considered in Final Findings.

ix) Investigation was carried out for the period starting from 1 April 2004 to 30th June 2005 (15 months) i.e. the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period 2001-02, 2002-03, 2003-04 and the POI.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION, LIKE ARTICLE AND DOMESTIC INDUSTRY:

PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

6. The product under consideration in the present application is Partially Oriented Yarn generally known as POY. It falls under the Custom Tariff Heading 5402.42 under the Indian Custom Tariff Classification. It is a yarn of polyester and is an intermediate, which is subject to further processing, for example, texturing or draw twisting, to make it suitable for weaving or knitting into fabrics. It has been contended by the importers

and users that the applicant has not specified the denier for which the anti-dumping duty is sought as the same are produced in a wide range. It has also been argued that the subject goods are manufactured from various processes and raw material and the subject goods should be classified as per the source raw material. On the other hand, it has been claimed by the applicants that the subject goods specified in the application cover all types of denier and there is no need that the denier of the subject goods is to be specified in the application. They have therefore contended that the submission of the importers and the users is baseless and devoid of any merit.

7. The issue raised by various interested parties have been examined and after examination, it is noted that the application by the domestic industry has been made covering all deniers. Further, the Designated Authority has also carried out the analysis considering the entire product under consideration. Therefore, the Authority does not find any merit in the argument of the importers for examining any particular denier of the product under consideration. With regards to the submissions of the interested parties that Teflon treated polyester yarns and polyester nano technology yarns are not produced by the petitioners and hence should be taken outside the scope of the product under consideration, it is noted by Authority that these yarns are not covered under the scope of POY as these products have been further processed. Further, it is also noted that there have been no submissions by the exporters from subject country with regards to the various grades and types/deniers of the product under consideration exported by them to India and that sold in the exporting country. Further, none of the importers have submitted any information along with the evidence to the Authority or requested the Authority for denier wise examination of the product under consideration. The Authority has considered the views expressed on the issue and holds that the product under consideration does not suffer from any infirmity as claimed by the importers/users. Therefore, the Authority does not find any merit in the argument of the importers/users. Thus, the product under consideration as defined in the provisional findings and as mentioned in the preceding paragraph is confirmed in the Final findings.

LIKE ARTICLE

8. Rule 2(d) of AD Rules defines Like Article as

"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."

The applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic

industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject good. The Authority notes that neither the exporters nor the interested parties have disputed the fact that there is any difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the domestic industry. The Authority observes that the imported goods are used by the user industry interchangeably with the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and produced by the subject countries being technically and commercially substitutable, are 'like articles' under the Anti Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'Like Articles' to the subject goods being imported from the subject country.

DOMESTIC INDUSTRY

9. Rule 2(b) defines domestic industry as under:-

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry:

It is noted that the application has been filed by M/s Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi on behalf of domestic industry comprising of the following producers of subject goods in India:

- I. Arfees Industries Ltd.
- II. Apollo Fibres Ltd.
- III. Central India Polyesters Ltd.
- IV. Century Enka Ltd.
- V. Filatex Industries Ltd.
- VI. Garden Silk Mills Ltd.
- VII. Indo Rama Synthetics (India) Ltd
- VIII. JBF Ltd.
- IX. Modern Petrofils Ltd.
- X. Nakoda Textiles Industries Ltd.
- XI. Recron Synthetics Limited
- XII. Welspun Syntex Ltd.

10. The Authority notes that the application has also been supported by the following producers:

- a. Reliance industries Ltd.
- b. Sanghi Polyesters Ltd.
- c. Nova Petrochemicals Ltd.
- d. Gokulanand Petrofibres

e. Rajvi Petrochem (P) Ltd.

11. During the provisional findings the Authority had noted that the collective production of the aforesaid producers constitutes a major proportion of the total domestic production of the like article and therefore they represented the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules supra. The Authority had also determined that aforesaid producers satisfy the criteria of standing to file the application on behalf of the domestic industry in terms of Rule 5(3). One of the interested parties has claimed that while determining the 'domestic industry', the imports from M/s Welspun have to be compared to their own production. The Authority notes that the importers have not advanced any convincing reasons in support of their argument. In any case, it is observed that the imports by M/s Welspun from China PR constitute approximately 0.1% of its own production, which is a miniscule quantity and can be ignored for the purpose of treating M/s. Welspun as part of the domestic industry.

Subsequent to the provisional findings, the interested parties have not placed any material fact before the Authority in respect of the issues raised by them regarding the standing of the applicants. Therefore, the Authority holds that the applicants meet the criteria of standing as laid down under the Rules and constitute the domestic industry for the purpose of this investigation in terms of Rule 2(b) of the Antidumping Rules.

C. PERIOD OF INVESTIGATION

12. Various interested parties have also stated that the POI should be taken as 12 months i.e. 2004-05 and not 15 months as taken by the Authority in this investigation. The issue has been examined and it is considered that it is the established practice of this Directorate to consider the period of investigation as latest as possible (to the date of initiation) and that the gap between the last day of the period of investigation and the date of initiation should not be more than 6 months. It is noted by the Authority that had the period of investigation been taken as 2004-05, the gap between the period of investigation and the date of initiation would have been more than 6 months and not in conformity with the policy. Thus, the Authority's decision to take POI of 15 months in this case is borne out of the practice of the Authority to keep the POI as close to the initiation as possible and in any case not later than 6 months from the date of POI and also taking into account easier availability of the information of the domestic industry in the form of the one full financial year. It was also noted that there are a large number of the domestic industries in this investigation and taking 9 months data out of the 12 months financial year data would have created difficulties for the Authority as well as to the domestic industry.

D. DUMPING MARGIN - NORMAL VALUE

13. The applicants have claimed that the subject country namely China is a non-market economy country under the Indian Anti-dumping Rules. Therefore, the normal value in case of China is required to be determined as per the procedure described in the para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. The applicants have claimed that as per paragraph 7, the normal value is required to be determined on any of the basis i.e domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export prices from such a third country to any other country including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

14. For the purpose of determination of normal value in case of a non market economy country, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative. It was proposed at the time of initiation that Chinese Taipei be taken as an appropriate market economy third country. The interested parties, namely M/s All India Texturiser's Association and M/s FIASWI in their submissions have submitted that the selection of Taiwan as surrogate country for the determination of normal value for China is not correct and normal value for China so determined on the basis of constructed normal value in Taiwan is far from reality. However, the interested parties in their submissions have not advanced any evidence before the Authority as to how and why Chinese Taipei cannot be taken as surrogate country and as to how the normal value for China as determined by the Applicant is not acceptable. It is noted that the domestic industry had requested that the unsubstantiated claims of the interested parties are required to be ignored.

Examination by the Authority

15. In anti-dumping investigations concerning imports from non-market economy countries, normal value is to be determined in accordance with paragraphs 7 & 8 of the Annexure 1 of the Anti-dumping Rules. The Authority notes that none of the Chinese producers has responded to the exporter's questionnaire. None of the Chinese producers have claimed that they should be granted market economy status. The Authority therefore proceeds to determine the normal value in accordance with paragraph 7 of Annexure 1 to the Rules.

16. It is noted that the normal value in China can be determined in the following manner:

- (a) on the basis of the price in a market economy third country, or
- (b) the constructed value in a market economy third country, or

- (c) the price from such a third country to other countries, including India.
- (d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

17. The Applicant had suggested Chinese Taipei to be taken as the third country market economy in terms of the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules. The Authority had also proposed Chinese Taipei as the appropriate third country market economy and had invited comments and information from all the interested parties at the time of initiation of investigation. However, in the absence of the response or information regarding the prevailing prices and costs in Chinese Taipei, it is not possible for the Authority to determine the normal value for China under the above-mentioned (a) to (c) methods as laid down in paragraph 7 of Annexure I to the Indian Anti-dumping Rules at present. Under the circumstances, for the purpose of these preliminary findings, the Authority had no alternative but to resort to determination of normal value for China on the basis of price paid or payable in India duly adjusted, as prescribed under the rules. While arriving at the normal value based on the price payable in India, the Authority had considered the international raw material prices while the consumption norms, conversion cost and other costs prevalent in India had been considered. A reasonable return had been added to the cost of production for arriving at the price payable in India. Subsequent to the preliminary findings, no comments have been made by any interested parties questioning the methodologies adopted by the Authority. In the absence of any substantive arguments, the Authority confirms the normal value arrived at by the Authority during the preliminary determination (with minor change). The normal value is, thus, determined as US \$ **** per MT.

EXPORT PRICE

18. In the application submitted for initiation of investigation, the applicant had worked out export price based on the DGCI&S import data. The Authority has also obtained the import data from DGCI&S and it was found during the preliminary findings that the volume and value of the imports under Custom Tariff Heading 5402.42 (which is a dedicated code for the product under consideration) is the same as was submitted by the applicants. During the public hearing and submissions made by the various interested parties, it was pointed out that while determining the volume and value of import, the Authority had taken into account

many transactions relating to the imports of yarns other than POY. After the preliminary findings, the Authority reexamined the transaction wise information pertaining to import of product under consideration from subject countries and it was found that though the ITC HS classification is a dedicated code for the product under consideration, it did have some transactions of spin drawn yarn and fully drawn yarn and others. After the examination, the Authority has reworked the volume and value of imports for subject goods from subject countries and following the reexamination, the CIF export price as per the DGCI&S import data was determined as Rs. **** per MT (US \$ **** per MT). After considering price adjustments on account of marine insurance, commission, ocean freight, bank charges & port expenses, the net export price is determined as US \$ **** per MT.

DUMPING MARGIN

19. For the purpose of a fair comparison between normal value and the export price, the Authority has determined both the normal value and export price at ex-factory level. Both the normal value and export price pertains to the same period. Both the prices are free of taxes. Thus, the Authority considers that the comparison made constitutes a fair comparison. Considering the normal value and the net export price determined as detailed above, dumping margin is determined as US \$ **** per MT which works out as 63% of net export price.

E. INJURY AND CAUSAL LINK

20. The domestic industry has submitted that share of imports from China has increased manifold not only in relation to total imports but also in comparison to total demand and total production during the period of investigation as compared to the base year April 01-March 02. It was submitted that the dumped imports from China have affected the domestic prices and the price undercutting and underselling is significant during the period of investigation. The domestic industry has alleged that the market share, capacity utilization, profitability, return on investment, cash flow, growth etc. have declined over the injury investigation period. The sales of the domestic industry have increased, however the increase in sales is less than the increase in demand. Further, the domestic industry had alleged that the margin of dumping from China is also significant during the period of investigation, which shows the difficulties being faced by the domestic industry in disposing of the subject goods.

21. On the other hand, the importers and the user associations submitted that the prices of POY have also come down for other countries and the demand for POY is high right from the year 2001-02 as compared to indigenous production and the indigenous industry has tremendously benefited by creating shortage. It has also been submitted that the decline in market share of the domestic industry is insignificant and sales

volume of the domestic industry has increased as a result of increase in demand. Further, it was also submitted that there is no injury with respect to employment and wages and as per the balance sheets of the domestic producers, they are not making losses and most of the companies are profit-making concerns.

22. The importers and user associations have also submitted that the inventories of the petitioners during the period of investigation were in fact lower than from the previous years. Further, the prices of raw material are low and POY prices are high in India as compared to China where raw material prices are high and POY prices are low. It was also held that almost all the companies are increasing their capacities which indicates that the import of POY has not affected the indigenous industry at all.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

23. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

24. The Authority has taken note of the arguments of the interested parties on injury examination aspect and addressed the issues raised at appropriate places in this disclosure statement to the extent these arguments are considered relevant to the investigations. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts before it and the arguments of the interested parties.

25. The Authority also notes that the Hon'ble Supreme Court, in the Reliance Industries Vs Designated Authority held that the Authority is required to carry out the determination of the injury and NIP for the 'domestic industry as whole' and not in respect of any particular company or enterprise. Therefore, in compliance with the above orders, the Authority called for cost and injury information from all the other known domestic producers. However, these producers have declined to provide any information on the above subject on the basis of their interpretation of the said judgment.

It has been argued by the other known producer (M/s RIL Ltd) that the said judgment of the Hon'ble Court does not require inclusion of all domestic producers in the NIP and injury determination. Further, the

other domestic producer has argued that the Designated Authority is interpreting the words "domestic industry as a whole" used by the Hon'ble Supreme Court in its judgment to mean the "domestic producers as a whole". In this connection, it has been submitted by M/s RIL that the Hon'ble Court in that judgment has held that the injury as well as NIP has to be determined for the "domestic industry as a whole" and not in respect of any particular company or enterprise. In the same paragraph, the Hon'ble Supreme Court refers to the definition of domestic industry under Rule 2(b). It has been added that throughout the discussions, the Supreme Court has used the words "domestic industry as a whole" and not "domestic producers as a whole". Further, at no stage has the Supreme Court held that the term "domestic industry" has to be interpreted in any manner different from the definition provided in Rule 2(b). On the other hand, the Court has clearly referred to the definition of "domestic industry" in the same paragraph.

26. The Authority notes that the above interpretation of the Judgment of the Hon'ble Court may not be in conformity with the said judgment as the review application filed by the Authority has been dismissed by the Hon'ble Court. Therefore, the Authority has proceeded with the determination of the injury and NIP for the domestic industry as a whole to include all domestic producers of the subject goods to the extent the same was reasonably available. It is noted that there are a number of other very small domestic producers apart from M/s Reliance Industries Ltd. who is one of the major producer of the subject goods in India having a share of approximately 33% in the total domestic production. The Authority has examined the cost and injury information of the major producer M/s Reliance Industries Ltd. from its Cost Audit Reports as available with the Cost Audit Branch of the Ministry of Company Affairs. For the other very small domestic producers, the cost and injury information is not available in the form of Cost Audit Reports or in any other form. It is also noted that these other very small producers collectively accounts for a share of 14% in the total domestic production. Therefore, the impact of these very small producers would not be significant. Accordingly, the injury examination has been carried out taking into account the information in respect of 11 known producers of the subject goods accounting for about 86% of the total domestic production in India. It is also noted that with respect to each of injury parameters 'domestic industry as a whole' includes the information of M/s Reliance industries Ltd. (with a total share of 86%) but not of all the producers in India. The term 'domestic industry' includes only the applicant producers (having a share of 52%). The injury analysis for all the injury parameters for the domestic industry as a whole could not be made as the requisite information for some of the injury parameters was not available with the Authority, which has been clearly indicated while making the injury analysis for each factor in the following paragraphs. However, M/s RIL Ltd has submitted costing information, which has been used for the calculation of non-injurious price of the domestic industry as a whole.

27. An analysis of the injury parameters as envisaged under the Rules has been carried out in the following paragraphs:

Volume of Imports

i) The Authority has examined the volume of imports from the subject country on the basis of the imports of subject goods as reflected by the official statistics published by the DGCI&S. As already mentioned earlier, the Authority has reexamined the transaction wise analysis of the imports of subject goods from subject countries and on the basis of reexamination, the figures of the volume and value of imports of subject goods have been revised. It is observed that the share of subject country in total imports has increased from 3.7%% in 2001-02 to 86% during the period of investigation. In absolute terms, the imports from the subject country has increased during the POI to a level of almost 22 times of the imports in the base year 2001-02 as is evident from the following table:

	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Imports from Subject Countries (MT)	1461	1455	8693	32132
Imports from Other Countries-Attracting ADD	33256	41046	15891	3856
Imports from Other Remaining Countries	4797	2886	2253	1413
Total Imports (MT)	39514	45387	26837	37401

%	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Imports from Subject Country (MT)	3.70	3.21	32.39	85.91
Imports from Other Countries-Attracting ADD	84.16	90.44	59.21	10.31
Imports from Other Remaining Countries	12.14	6.36	8.40	3.78
Total Imports (MT)	100.00	100.00	100.00	100.00

Market share of Imports from subject country in the total imports and demand

ii) The Authority finds that the imports from China in comparison to total demand in India have increased from a low level of 0.23% during 2001-02 to 4.19% during the period of investigation. The trend in percentage increase from year to year is as under:

Total Demand				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Total Demand (MT)	646810	683470	708597	766477
Trend	100	106	110	119

Share of Imports				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Imports from Subject Country (MT)	1461	1455	8693	32132
Imports from Other Countries-Attracting ADD	33256	41046	15891	3856
Imports from Other Remaining Countries	4797	2886	2253	1413
Total Imports (MT)	39514	45387	26837	37401
Total Domestic Sales (MT)	642012	680584	706344	765063
Total Demand (MT)	646810	683470	708597	766477
% Share of Imports from China in:				
Total Imports	4%	3%	32%	86%
Total Demand (MT)	0.23%	0.21%	1.23%	4.19%
% Share of Imports from Other Countries attracting ADD in:				
Total Imports	84.16%	90.44%	59.21%	10.31%
Total Demand (MT)	5.14%	6.01%	2.24%	0.50%
% Share of Imports from Other Remaining Countries in:				
Total Imports	12.14%	6.36%	8.40%	3.78%
Total Demand (MT)	0.74%	0.42%	0.32%	0.18%

Imports from subject country as % of domestic production:

iii) The Authority notes that imports from China as percentage of domestic production of the domestic producers have increased manifold from a level of 0.19% in the year 2001-02 to 3.43% during the period of investigation. Thus, the imports from the China have increased not only in absolute terms but also as a share to total imports into India, market demand and also domestic production.

Share of Imports	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Imports from Subject Countries (MT)	1461	1455	8693	32132
Imports from Other Countries-Attracting ADD	33256	41046	15891	3856
Imports from Other Remaining Countries	4797	2886	2253	1413
Total Imports (MT)	39514	45387	26837	37401
Total Domestic Sales (MT)	642012	680584	706344	765063
Total Demand (MT)	646810	683470	708597	766477
Total Domestic Production	784460	840065	900245	936775
% Share of Imports from China in:				
Total Imports	4%	3%	32%	86%
Total Demand (MT)	0.23%	0.21%	1.23%	4.19%
Total Domestic Production	0.19%	0.17%	0.97%	3.43%

Effect of Dumped Imports on prices in the domestic market for like products:Price Undercutting

iv) With regard to the effect of the dumped imports on domestic prices, it has been examined whether there has been a significant price

undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. A comparison for product concerned was made between the landed value of exported product and the average selling price of the domestic industry for domestic market net of all rebates and taxes for sales made to unrelated customers, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level. The CIF prices of the subject country concerned were adjusted for post importation applicable duties. This comparison showed that during the period of investigation, the subject goods originating in subject country was sold in the Indian market at prices which undercut the domestic industry's prices when expressed as a percentage of the domestic selling prices of the domestic industry as is evident from the table below.

In order to assess the effect of imports on the domestic market an analysis of import prices over the injury period was made. It was noted that the exporters from subject country have decreased their prices and the landed value has declined by 9% over the injury period. Though the domestic selling prices have also increased during this period by ****%, price undercutting has significantly increased during the injury period and remains significant during the POI

Price Undercutting	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Selling Price Rs. / MT-Domestic Industry as a Whole	****	****	****	****
Indexed	100	112	120	130
Landed Value from Subject Countries Rs. / MT	****	****	****	****
Indexed	100	110	85	91
Price Undercutting Rs. / MT	****	****	****	****
Price Undercutting (%)	****	****	****	****
Price Undercutting (%)	-12% to 1%	-8 to 5%	16% to 30%	20% to 48%

)-Range				
---------	--	--	--	--

Price depression and Suppression

v) There has been no decline in the selling price of the domestic industry during the injury period. Therefore no price depression has been caused to the domestic industry. However, it is seen that the landed price from subject countries have consistently declined from subject country and also the cost of the production has also shown corresponding increase with the domestic selling price (marginally more than the increase in the domestic selling price) implying that the domestic industry has suffered price suppression on account of dumped imports from subject country.

	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Cost of Production Rs. / MT-Domestic Industry as a Whole	****	****	****	****
Indexed	100	108	104	132
Increase Year to Year		****	****	****
Indexed		100	-58	591
Selling Price Rs. / MT-Domestic Industry as a Whole	****	****	****	****
Indexed	100	112	120	130
Increase Year to Year		****	****	****
Indexed		100	76	112
Landed Value from Subject Countries Rs. / MT	56137	61537	48429	50997
Indexed	100	110	86	91

Price underselling

vi) The Authority has also examined the claim of the petitioner that the domestic industry is suffering on account of the price underselling from the sale of subject goods. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the Non-injurious price for the product under consideration and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant level of incidence of price underselling causing injury to the domestic industry from the dumped imports from subject country.

Price Underselling	POI (Annualised)
Non Injurious Price Rs. / MT	
Landed Value from China Rs. / MT	50996
Price Underselling Rs. / MT	****
Price Underselling (%)	****
Price Underselling (%) -Range	25% to 40%

Situation of the Domestic Industry

vii) For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra. In line with the Supreme Court Judgment, the Authority has proceeded with the determination of the injury and NIP for the domestic industry as a whole to include all domestic producers of the subject goods to the extent the same was relevant and reasonably available. It is noted that there are a number of other very small domestic producers apart from M/s Reliance Industries Ltd. who is one of the major producer of the subject goods in India having a share of approximately 33% in the total domestic production. The Authority has examined the cost and injury information of the major producer M/s Reliance Industries Ltd. from its Cost Audit Reports as available with the Cost Audit Branch of

the Ministry of Company Affairs. For the other very small domestic producers, the cost and injury information is not available in the form of Cost Audit Reports or in any other form. It is also noted that these other very small producers collectively accounts for a share of 14% in the total domestic production. Therefore, the impact of these very small producers would not be significant. Accordingly, the injury examination has been carried out taking into account the information in respect of 11 known producers of the subject goods accounting for about 86% of the total domestic production in India. It is also noted that with respect to each of injury parameters 'domestic industry as a whole' includes the information of M/s Reliance industries Ltd. but not of all the producers in India. The term 'domestic industry' includes only the applicant producers. The injury analysis for all the injury parameters for the domestic industry as a whole could not be made as the requisite information for some of the injury parameters was not available with the Authority, which has been clearly indicated while making the injury analysis for each factor in the following paragraphs.

Sales and Market share of domestic producers:

viii) It is noted that sales of the domestic industry have increased and domestic industry as a whole have increased and the increased is in line with the increase in demand. Further, the Authority finds that the market share of the domestic industry and the imports from the subject countries in the demand of subject goods in India has been as under:

Sales (MT)				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Domestic Industry	307826	310022	324328	392195
Other Domestic Producers	202429	175147	234039	231456
Domestic Industry as a Whole	510255	485169	558367	623651

Market Share of
Domestic
Industry

	April 01 to	April 02	April 03	POI
--	--------------------	-----------------	-----------------	------------

	March 02	to March 03	to March 04	(Annualised)
Sales (MT):				
Domestic Industry	307826	310022	324328	392195
Other Domestic Producers	202429	175147	234039	231456
Domestic Industry as a Whole	510255	485169	558367	623651
Total Demand (MT)	646810	683470	708597	766477
Market Share of:				
Domestic Industry (%)	48	45	46	51
Other Domestic Producers (%)	31	26	33	30
Domestic Industry as a Whole (%)	79	71	79	81

The Authority finds that the share of the domestic producers have increased marginally from 48% during 01-02 to 51% during the POI while the share of the domestic industry as a whole has increased by 2 percentage points over the same period. It is also noted that over the same period the demand has grown by 18%. It shows that the domestic industry was able to achieve growth though marginally during the injury period.

Production & Capacity Utilization:

ix) The production and capacity utilization of the domestic industry has been as under:

Production (MT)				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Domestic Industry	385167	402651	423669	484734
Other Domestic Producers	269188	247679	255620	252412
Domestic Industry as a Whole	654355	650330	679289	737146

Capacity (MT)

	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Domestic Industry	389425	428175	478196	513208
Other Domestic Producers	267174	275274	268450	261979
Domestic Industry as a Whole	656599	703449	746646	775188

Capacity Utilisation%				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Domestic Industry	98.91%	94.04%	88.60%	94.45%
Other Domestic Producers	100.75%	89.98%	95.22%	96.35%
Domestic Industry as a Whole	99.66%	92.45%	90.98%	95.09%

The Authority finds that the capacity utilization of the domestic industry has declined from 98.91% in the year 2001-02 to 94.45% during the period of investigation. Thus, the decline of in the capacity utilization and on the other hand increase in dumped imports from subject country over the injury investigation period appears to have adversely affected the domestic industry.

Inventories:

x) The Authority notes that the level of inventories of the domestic industry has come down during the period of investigation while the inventories as a percentage of sales declined significantly during the injury period.

<u>Inventories</u>				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Sales (MT)- Domestic Industry	307826	310022	324328	392195
Inventories- Domestic Industry	29632	29605	21878	6887

Inventories as percentage of Sales	9.63%	9.55%	6.75%	1.76%
Indexed	100	99	70	18

Factors affecting Domestic Prices:

xi) The Authority notes that the level of price undercutting from subject country is significant as a result of dumped imports. Further, price underselling is also evident as the landed value of imports from China is significantly lower than the non-injurious price of the domestic industry. The landed value/MT of imports from China has declined drastically during the period of investigation as compared to the year 2002-03 whereas at the same time the cost of raw material has increased as a result of the soaring crude oil prices. The Authority notes that apart from the applicants there are few other domestic producers of the subject goods in the domestic market in India catering to about 48% of the total production. The data of these producers (covering 33% of the total production) do not show significant cost and price difference between the domestic producers. However, the injury investigation has been carried out for the domestic industry as a whole, including the other known producers. The Authority also notes that the dumped imports from the subject countries have been found to have significant price undercutting and underselling effect on the domestic industries prices. With regard to selling prices of the domestic industry, it is noted that the same have increased during the period of investigation as compared to the base year. Thus, the principal factor affecting the domestic prices appear to be the dumped prices of the subject goods from the subject country.

Magnitude of Margin of Dumping:

xii) The Authority finds that the magnitude of the margin of dumping for subject goods from the subject country is significant.

Employment, Wages and Productivity :

xiii) The Authority notes that the domestic industry has added additional capacity and employed a number of persons. Accordingly, number of employees and wages paid to them has gone up during the injury investigation period. The Authority finds that the productivity per employee during the period of investigation has increased as compared to base year 2001-02.

Employees, Wages and Productivity

	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Employees (Nos.)- Domestic Industry	3254	3398	3434	3758
Wages (Rs. Lacs)- Domestic Industry	3413	3521	3825	4495
Production of Domestic Industry	385167	402651	423669	484734
Productivity per employee / MT	118	118	123	129

Profitability:

xiv) The Authority notes that the domestic industry has not been able to achieve profits during the period of investigation. The Domestic Industry achieved a level of profit of 1.30% in the year 2001-2 which however, came down to a negative level of (0.80%) during the period of investigation as may be seen from the table given hereunder:

Profit /Loss (Rs. Lacs):				
Domestic Industry	****	****	****	****
Other Domestic Producers	****	****	****	****
Domestic Industry as a Whole	****	****	****	****
Indexed:				
Domestic Industry	100	261	603	-103
Other Domestic Producers	-100	-66	198	-62
Domestic Industry as a Whole	-100	-27	359	-96
Profit /Loss (%):				
Domestic Industry	****	****	****	****
Other Domestic Producers	****	****	****	****
Domestic Industry as a Whole	****	****	****	****

Return on Investment (Capital Employed):

xv). The Authority notes that return on capital employed has also declined and followed the same trend as that of profitability. The domestic industry could earn ****% return on its investment during the period of investigation whereas it earned : ****% return in the previous year 2003-04 and ****% during the base period.

Return on Capital Employed				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI
Capital Employed (Rs. Lacs)-Domestic Industry	****	****	****	****
Indexed	100	121	102	102
Profit / Loss before Interest (Rs. Lacs)-Domestic Industry	****	****	****	****
Indexed	100	98	134	25
ROCE (%) -Domestic Industry	****	****	****	****
Indexed	100	80.94	131.04	18.66

Actual and potential negative effect on cash flows:

xvi) The Authority finds that the cash profit / cash flow has also followed the same trend as that of the profitability and during the period and it has come down significantly during the POI as compared to the base year 2001-02.

Cash Profit				
	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Cash Profit (Rs. Lacs)-Domestic Industry	****	****	****	****
Indexed	100	138	190	87
Cash Profit of Other Known Producer	****	****	****	****
Indexed	-100	-7	1337	9
Domestic Producer as a whole	****	****	****	****
Indexed	100	165	509	107

Growth:

xvii) The Authority notes that though the sales volume of the domestic industry has gone up during POI, yet growth in sales volume during POI is less than the previous year and growth in the total demand over the same period. Besides market share of the domestic industry has declined during the POI as compared to the preceding year

Growth	April 01 to March 02	April 02 to March 03	April 03 to March 04	POI (Annualised)
Demand		6	10	19
Production-Domestic Industry as a Whole		-1	4	9
Market Share-Domestic Industry as a Whole		-10	-0.11	3
Sales Volume-Domestic Industry as a Whole		-5	15	12
Profit- Domestic Industry as a whole		-28	336	-89
Cash Flow / MT-Domestic Industry as a whole		65	208	-79
ROCE-Domestic Industry		-19	62	-86

Ability to Raise Capital Investments:

xviii). The Authority finds that in view of the losses being suffered by the domestic industry on the product under consideration during the POI, the ability of the domestic industry to raise capital investment may be adversely affected in view of the negative profits of the domestic industry and declining returns during the period of investigation.

F. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

Effect of dumped imports

28. Between 2001-02 and the POI, the dumped imports from subject country as percent of total import of subject goods have

increased sizably from 4% to 86%. The percentage share of imports from china in comparison to total demand has also been going up over the investigation period. This increased from 0.23% in 2001-02 to 4.19% in the POI. While examining the price effect i.e. whether the dumped imports have significantly undercut the price of the subject good in India, the Authority found that the landed value of the subject goods from china was lower than the selling price of the domestic industry thereby undercutting the selling price of the domestic industry significantly. It is found that the price undercutting and the pricing behaviour of landed value of imports has forced the domestic industry to keep the domestic prices at an unremunerative level even below the cost of production thereby adversely affecting the financial condition of the domestic industry. The domestic industry could not increase the selling price to recover the full increase in cost of production due to dumped imports and had to suffer financial losses during the POI. The undercutting along with price suppression in effect eroded the profitability of the domestic industry. Further, the decline in profitability to a negative level of profitability in the POI as compared to positive profitability in the base year 2001-02 is a clear indicator of injury to the domestic industry. The Authority notes that the profits in the year 2003-04 has been higher as compared to other years of the injury investigation period, the increase in the profitability in that year is mainly because of the fact of low level of imports from China which may have allowed the domestic industry to realise better prices and improved margins in the domestic market. The profitability of the domestic industry in the immediate next year i.e. POI has sharply declined in view of the spurt in imports at highly dumped prices from China by about four times over the same period as mentioned above. On the basis of the foregoing, it is held that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports from China PR during the POI.

G. EFFECT OF OTHER FACTORS

Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers:

29. The Authority did not find any trade restrictive practices followed by the Indian producers and other competing industries. As regards the Domestic Industry's inability to fill the gap between the domestic demand and their own production, it is observed that the imposition of anti-dumping duties does not amount to any kind of restriction on suppliers and producers for supplying the subject goods in the domestic market, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption:

30. It is noted that there is no contraction in the demand during the period under consideration. On the contrary, the overall demand has increased during the POI. Therefore, the possible decline in demand is not a factor which could have caused injury to the domestic industry

Technology:

31. None of the interested party has submitted any evidence that the technology is a factor of injury to the domestic industry.

Export performance:

32. The Domestic Industry has exported the subject goods during the period of investigation as well as during previous years. The Authority notes that the export performance of the domestic industry has shown improvement. The profitability of the domestic and exports sales have been segregated for the purpose of the injury examination. Therefore, injury caused due to exports (if any) has not been attributed to the performance of the domestic industry in the domestic market.

Productivity:

33. The productivity of the domestic industry has improved during the period of investigation as compared to the base year 2001-02. The productivity *per se* could not be the cause of injury to the domestic industry.

Other arguments

34. It has been submitted by some interested parties that demand for POY is high right from the year 2001-02 as compared to indigenous production and the indigenous industry has tremendously benefited by creating shortage. The Authority has examined this statement and notes that the associations have merely made statements without evidence or cogent reasoning in support of their argument. With regards to their other arguments that as per the balance sheets of the domestic producers, they are not making losses and most of the companies are profit-making concerns, it is noted that anti-dumping investigations are product specific and any conclusions based on the balance sheet of the company which contains the information for other products also, is not appropriate. This position is clear from the plain language of the anti-dumping laws and the

pronouncement of the Appellate Tribunal also. With regards to the submissions of the interested parties that almost all the companies are increasing their capacities, which indicate that the import of POY has not affected the indigenous industry at all, it is noted that some of the applicants are indeed increasing their capacities, the fact which the interested parties have also admitted. It is also noted that the domestic industry has submitted that the decision to increase capacities was taken prior to the initiation of investigation and there is a specific lead time during which the domestic industry faced the injurious effect of dumping from China. The issue has been examined and it is noted that capacities are added to take advantage of the growing market and economies of scale. Therefore, the mere fact that some components of the domestic industry have increased their capacities may not lead to the conclusion that they may not be suffering on account of the dumped imports from subject country. With regards to the submission of various interested parties that the excise duty on POY has been reduced over the years and the same has not been passed on to customers, it is noted that the analysis of the selling prices is always made at the ex-factory level. The ex-factory price does not include any element of excise duty or the expenses after clearance from the factory. Therefore, the statement of the federation has not been found relevant in this investigation.

H. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINK:

35. In view of the foregoing the Authority considers that the quantum of dumped imports of subject goods from the subject country have increased in absolute terms as well as in relation to total demand and domestic production in India. However, parameters such as market share of the domestic industry in the total demand, sales, production, inventory have not shown any decline indicating that the absence of any significant volume injury to the domestic industry and also to domestic industry as a whole. However, the domestic industry has suffered significantly on account of the price effects as the price undercutting which was negative during the base year became positive and significant during the POI. The landed prices of the dumped subject goods from the subject country have shown a consistent decline in spite of the increase in the cost of production of the domestic industry indicates price suppression. It is also noted that the profitability of the domestic industry for product under consideration has become negative during the period of investigation and the return on investment and cash flows have been adversely affected and declined to a meager level in the period of investigation. The dumping margin from the subject country is considered significant. On the basis of the foregoing, it is held that the domestic industry has suffered material injury as envisaged under the Rules. No

other factor, other than the dumped imports from subject country, have been brought to the notice of the Authority, that could have caused injury to the domestic industry

36. In view of the above the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and the injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

Determination of Non-injurious price

37. The Authority determined the non-injurious price for the domestic industry as a whole in accordance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India as quoted earlier and a detailed disclosure of the methodology of determination of the NIP was made to the domestic industry.

38. The Authority notes that the Non-injurious price of the domestic industry as a whole has been determined in accordance with the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India taking into account the guidelines and methodology set by the Hon'ble Supreme Court of India and the weighted average NIP for the domestic industry as a whole as been determines as Rs ****/ MT.

39. The non-injurious price determined by the Authority is the weighted average of all types of the subject goods produced by the domestic industry and the same has been compared with the weighted average landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject countries and the injury margins have been worked out as follows:

Injury Margin Calculations		
Name of company	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin %
All Producers and exporters from China PR	****	30-40%

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

40. The Authority holds that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by

the unfair trade practices of dumping so as to facilitate re-establish a situation of open and fair competition.

41. The Authority also recognizes that though the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by these anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would eliminate the unfair advantages gained by the dumping practices and would prevent the decline of the domestic industry and help in maintaining availability of wider choice of the subject goods to the consumers.

K. Conclusions:

42. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a. Subject goods originating in or exported from subject country have been exported to India below their normal values.
- b. The domestic industry has suffered material injury.
- c. The injury has been caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods originating in or exported from the subject country.
- d. The Authority thus considers necessary to recommend definitive anti-dumping duty on imports of subject goods falling under Chapter 54 of Customs Tariff Act originating in or exported from the subject country.

L. Recommendations:

43. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a final investigation into dumping, injury and causal link between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having definitively established positive dumping margin against the subject country, as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that

imposition of definitive duty is required to offset dumping and injury.

44. Therefore, Authority considers it necessary to recommend definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

45. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975. Accordingly, definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Column 9 of the table below is recommended on all imports of Partially Oriented Yarn (POY) falling under chapter 54 of Custom Tariff Classification Act 1975, originating in or exported from China PR.

Sl. No	Sub-headin g	Descrip tion of goods	Speci ficati on	Countr y of origin	Countr y of Export	Produc er	Export er	Amo unt	Unit of Meas urem ent	Curren cy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	5402.4 2	Partiall y Oriente d Yarn — All Types	Any	China PR	Any	Any	Any	545.2 2	MT	US\$
2.	-do-	-do-	-do-	Any	China- PR	Any	Any	545.2 2	MT	US\$

M FURTHER PROCEDURE

46. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

47. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

R. GOPALAN, Designated Authority